कानपुर, मंगलवार, 16 जून, 2026
वर्ष: 03, अंक: 147, पृष्ठ: 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

इनसाइड गुरुवार को शहर आएंगे सीएम योगी... >Pg03

अमेरिका का विमान क्रैश, 8 की मौत... >Pg12

मूल्य: 2 ₹

मेट्रो नेटवर्क का महाविस्तार

लखनऊ मेट्रो का मेगा ब्लूप्रिंटः बाराबंकी, उन्नाव और संडीला तक दौड़ेगी रफ्तार

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेट्रो रेल नेटवर्क के सबसे बड़े विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (क्व्क्र्र्ष्ट) ने अगले दस वर्षों में राजधानी और उससे जुड़े आसपास के क्षेत्रों को आधुनिक मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने का खाका तैयार किया है। प्रस्तावित योजना के तहत वर्तमान एयरपोर्ट-मुंशी पुलिया कॉरिडोर का विस्तार करते हुए मेट्रो को पीजीआई, मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब (बीकेटी), इटौंजा, बाराबंकी, उन्नाव और संडीला तक पहुंचाया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार राजधानी में कुल 10 नए मेट्रो कॉरिडोर विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 30 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। योजना को चरणबद्ध तरीके से अगले दस वर्षों में पूरा किया जाएगा। मेट्रो विस्तार से लखनऊ महानगर के साथ-साथ आसपास के जनपदों के करीब 35 से 40 लाख लोगों को बेहतर और तेज सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।

परियोजना के दूसरे चरण की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और जुलाई से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। प्रस्तावित विस्तार में पीजीआई से मोहनलालगंज तथा बाराबंकी की ओर नई लाइन विकसित की जाएगी। वहीं उत्तर दिशा में मेट्रो को बीकेटी और इटौंजा तक ले जाने की योजना है। पश्चिमी दिशा में उन्नाव और संडीला को भी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने का खाका तैयार किया गया है।

मेट्रो स्टेशनों को मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग, ई-बाइक, ई-साइकिल, फीडर बस सेवा और स्मार्ट टिकटिंग जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी और शहर में ट्रैफिक जाम तथा प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद है। शहरी विकास विभाग का मानना है कि बढ़ती आबादी और तेजी से फैलते शहरी

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मिलेगा नया आयाम

लखनऊ मेट्रो का विस्तार केवल शहर तक सीमित नहीं रहेगा। बाराबंकी, उन्नाव और संडीला जैसे शहरों के जुड़ने से दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे राजधानी और आसपास के जिलों के बीच आवागमन तेज होगा तथा आर्थिक गतिविधियों को भी नया बल मिलेगा।

रियल एस्टेट बाजार में आएगी तेजी

मेट्रो कॉरिडोर के आसपास स्थित क्षेत्रों में भूमि और आवासीय परियोजनाओं की मांग बढ़ने की संभावना है। मोहनलालगंज, बीकेटी और इटौंजा जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ सकता है। बेहतर परिवहन सुविधा से नए आवासीय और व्यावसायिक केंद्र विकसित होंगे।

क्षेत्र को देखते हुए मेट्रो नेटवर्क का विस्तार भविष्य की जरूरत है। नई लाइनों के निर्माण से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और राजधानी के आसपास विकसित हो रहे नए आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद लखनऊ उत्तर भारत के सबसे व्यापक मेट्रो नेटवर्क वाले शहरों में शामिल हो सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से लाखों लोग निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन अपनाएंगे। इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव घटेगा, ईंधन की खपत कम होगी और राजधानी में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

नीट-यूजी री-एग्जाम 21 जून को, पेपर लीक रोकने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा कवच

➪ केंद्र सरकार का बड़ा कदम, टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाई गई अस्थायी रोक

➪ एनटीए और प्रशासन हाई अलर्ट पर, लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा पर देश की नजर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। नीट-यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। पेपर लीक और नकल के आरोपों के चलते मई में हुई परीक्षा रद्द होने के बाद केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और राज्यों के प्रशासन ने इस बार अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए केंद्र ने देशभर में टेलीग्राम की सेवाओं पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि कुछ संगठित गिरोह इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल फर्जी प्रश्नपत्र बेचने और लीक की अफवाहें फैलाने के लिए कर रहे थे।

एनटीए के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर बहुस्तरीय निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्य जांच, 90 दिनों तक फुटेज सुरक्षित रखने, मॉक ड्रिल, बिजली बैकअप और मेडिकल इमरजेंसी जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। परीक्षा से पहले और बाद में सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी करेंगी।

गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित नीट-यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक विवाद में घिर गई थी। जांच के बाद केंद्र सरकार और एनटीए ने परीक्षा रद्द कर 21 जून को पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया। इसके बाद सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कथित प्रश्नपत्र बिक्री और लीक के कई दावे सामने आए, जिन्हें ह्रञ्ज ने पूरी तरह फर्जी

बताते हुए छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी। देशभर के लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार का दावा है कि इस बार किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, नकल या परीक्षा प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सीएम ग्रिड योजना में पलीता लगा रहे जल निगम और केस्को

» सीएम ग्रिड सड़क निर्माण को लेकर पर नगर आयुक्त ने स्थल निरीक्षण कर लापरवाही पर कार्रवाई के दिए निर्देश

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर निगम की महत्वाकांक्षी सीएम ग्रिड रोड परियोजना में हो रही देरी और विभागीय लापरवाही पर नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने कड़ा रुख अपनाया है। जोन-3 क्षेत्र में सीएम ग्रिड रोड का औचक निरीक्षण करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों को समयबद्ध ढंग से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए और शिथिलता बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए।

निरीक्षण के दौरान मार्बल मार्केट से अलंकार गेस्ट हाउस तक निर्माणाधीन सड़क का जायजा लेते हुए नगर आयुक्त ने पाया कि जल निगम, जलकल विभाग और केस्को के अधूरे कार्यों के कारण परियोजना प्रभावित हो रही है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने तीनों विभागों को दो दिन के भीतर अपने सभी लंबित कार्य पूर्ण कर अभियंत्रण विभाग को स्थल हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। साथ ही फुटपाथ और अन्य शेष निर्माण कार्य 10 दिनों में पूरा करने की समयसीमा तय की।नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा मुख्य अभियंता को कार्यों की नियमित निगरानी कर समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए।

12.42 करोड़ की परियोजना में 9 माह बाद भी काम शुरू नहीं

निरीक्षण के दौरान बाबा कुटी स्थित जलकल कार्यालय परिसर में प्रस्तावित जोनल कार्यालय-3 एवं सह-कार्यस्थल निर्माण परियोजना की प्रगति भी परखी गई। लगभग 12.42 करोड़ रुपये लागत वाली इस परियोजना में 9 माह बीत जाने के बावजूद कार्य शुरू न होने पर नगर आयुक्त ने गहरी नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने पाया कि जलकल विभाग द्वारा पाइप लाइन नहीं डाली गई है, जल निगम ने कार्य शुरू नहीं किया है और केस्को द्वारा बिजली के पोल भी शिफ्ट नहीं किए गए हैं। इस पर नगर आयुक्त ने तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा पूरे मामले से नगर विकास विभाग को अवगत कराने के निर्देश दिए।

मुख्य अभियंता को 10 दिन के भीतर जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही परियोजना को तत्काल शुरू कर निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने के निर्देश भी दिए गए।

जनसुनवाई शिविर में 13 शिकायतों का मौके पर निस्तारण, नागरिकों की समस्याएं सुनकर दिए त्वरित समाधान के निर्देश

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। प्रधानमंत्री के 12 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित जनसुनवाई अभियान के अंतर्गत नगर निगम जोन-3 द्वारा किदवई नगर स्थित म्यूजिकल फाउंटेन पार्क में जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आमजन की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

शिविर में नगर निगम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पशुपालन विभाग, नंद बाबा दुग्ध मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, बेसिक शिक्षा विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा स्वरोजगार योजनाओं से संबंधित शिकायतें और आवेदन प्राप्त हुए। कुल 13 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।जनसुनवाई के दौरान नागरिकों ने पेयजल, सफाई, आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। अधिकारियों ने अधिकांश मामलों में मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया, जबकि शेष शिकायतों के शीघ्र निस्तारण का भरोसा दिलाया।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों की भी सहभागिता रही। उपस्थित लोगों ने कहा कि ऐसे शिविरों से आमजन को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है, जिससे समाधान की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनती है।

जोन-3 प्रशासन ने नागरिकों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तथा अपनी समस्याओं के समाधान हेतु जनसुनवाई शिविरों में सक्रिय सहभागिता करने की अपील की है। जनसुनवाई शिविर के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

आईआईटी कानपुर का स्पेस मिशन, स्टार्टअप को मिले 10 करोड़

स्वदेशी ग्रीन प्रोपल्शन तकनीक से अंतरिक्ष क्षेत्र में नई छलांग

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक और स्टार्टअप अब भारत की अंतरिक्ष तकनीक को नई दिशा देने की तैयारी में हैं। संस्थान के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर से जुड़े स्टार्टअप ड्रीम एयरोस्पेस को स्वदेशी उपग्रह प्रोपल्शन तकनीक विकसित करने और उसके व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। यह फंड चंडीगढ़ एंजेल्स नेटवर्क की ओर से उपलब्ध कराया गया है।

स्टार्टअप इस राशि का उपयोग अपने एटम सीरीज थ्रस्टर और क्यूबहुड प्रोपल्शन मॉड्यूल के फ्लाइट क्वालीफिकेशन और अंतरिक्ष परीक्षणों को पूरा करने में करेगा। ड्रीम एयरोस्पेस ने अनुसंधान के जरिए पर्यावरण अनुकूल ग्रीन प्रोपल्शन तकनीक विकसित की है, जो उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों को स्वच्छ एवं सुरक्षित ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है।

इससे अंतरिक्ष अभियानों में विषैले उत्सर्जन और अंतरिक्ष मलबे को कम करने के साथ उपग्रहों की कार्यक्षमता और आयु भी बढ़ाई जा सकेगी।

कंपनी ने पारंपरिक और अत्यधिक विषैले हाइड्राजीन ईंधन के विकल्प के रूप में हाइड्रॉक्सिल अमोनियम नाइट्रेट आधारित हरित ईंधन विकसित किया है। इसके अलावा क्यूबहुड प्रोपल्शन मॉड्यूल का पहला इन-ऑर्बिट डेमोंस्ट्रेशन भी प्रस्तावित है, जो भारतीय अंतरिक्ष तकनीक के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकता है।

इधर, आईआईटी कानपुर के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग ने अपने पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए वॉक-इन एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 जून निर्धारित की गई है, जबकि ऑनलाइन साक्षात्कार 18 जून को होंगे। चयनित शोधार्थियों को 42 हजार रुपये प्रतिमाह तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी।

संस्थान के अनुसार शोधार्थियों को एयरोडायनामिक्स, प्रोपल्शन, फ्लाइट डायनेमिक्स एंड कंट्रोल, स्ट्रक्चर्स एंड एयरोइलास्टिसिटी, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स तथा एरो-थर्मोडायनामिक्स जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में शोध कार्य करने का अवसर मिलेगा। आईआईटी कानपुर की यह पहल अंतरिक्ष अनुसंधान और स्वदेशी तकनीकी विकास को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

प्रेम प्रसंग के विवाद में पति की हत्या

पत्नी ने पेट में घोंपा चाकू

❍ फीलखाना के बालाजी धाम अपार्टमेंट की घटना

❍ प्रेमी से बातचीत का विरोध करने पर हुआ खूनी विवाद

❍ पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। फीलखाना थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद ने ऐसा भयावह मोड़ ले लिया कि एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रेम प्रसंग को लेकर लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच पत्नी ने कथित तौर पर पति पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पति ने कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष किया, लेकिन अंतत: उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

आरोपी पत्नी निहारिका

मृतक की फाइल फोटो और जानकारी देते परिजन

जानकारी के अनुसार, फीलखाना स्थित बालाजी धाम अपार्टमेंट निवासी 45 वर्षीय मनीष गुप्ता कपूर कपड़ों के कारोबार से जुड़े थे। परिवार में उनकी मां मीरा गुप्ता, पत्नी निहारिका और पुत्र रियाश हैं। मृतक के पिता रामकिशोर गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मनीष ने वर्ष 2017 में निहारिका से प्रेम विवाह किया था।

शुरुआती वर्षों में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन करीब दो वर्ष पूर्व मनीष को पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद दंपती के बीच अक्सर विवाद होने लगा था।

परिजनों के अनुसार, 5 जून को निहारिका किसी व्यक्ति से फोन पर बातचीत कर रही थी। मनीष ने इस पर आपत्ति जताई और बातचीत बंद करने को कहा।

इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर निहारिका गुस्से में किचन गई और वहां से चाकू लाकर मनीष के पेट में वार कर दिया। चाकू लगते ही मनीष लहूलुहान होकर गिर पड़े। घटना के बाद परिजन उन्हें तत्काल केपीएम अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया। कई दिनों तक चले इलाज के बावजूद मंगलवार को मनीष ने दम तोड़ दिया।

> **पीड़ित परिवार की शिकायत पर हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी पत्नी निहारिका को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।**
>
> **– अभय नारायण**
> **फीलखाना थाना प्रभारी**

गुरुवार को शहर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

सीएसए में प्राकृतिक खेती सम्मेलन में करेंगे शिरकत

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को उन्नाव और कानपुर के दौरे पर रहेंगे। उन्नाव में जनसभा को संबोधित करने के बाद वह कानपुर पहुंचेंगे, जहां प्राकृतिक खेती सम्मेलन में भाग लेने के साथ ही कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों में तैयारियां तेज हो गई हैं।

➪ करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और पीडब्ल्यूडी कार्यों की समीक्षा भी करेंगे

मुख्यमंत्री का पहला कार्यक्रम चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में आयोजित प्राकृतिक खेती सम्मेलन होगा। सम्मेलन में किसान, कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। किसानों से संवाद का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है।

इसके बाद मुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन सड़कों, पुलों तथा अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अधूरी और धीमी गति से चल रही परियोजनाओं पर अधिकारियों से जवाब-तलब कर सकते हैं तथा समयबद्ध गुणवत्ता पूर्ण कार्यों के निर्देश देंगे।

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री गोविंद नगर और कल्याणपुर क्षेत्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने से यातायात व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जल निकासी की समस्या कम होगी और नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा। कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी रहने की संभावना है।

मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय होते ही प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने देर शाम अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, कार्यक्रम स्थलों की तैयारियों और विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़े सभी इंतजाम निर्धारित समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरे कर लिए जाएं।

नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में 722 हरे पेड़ कटने पर निदेशक सस्पेंड

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (एनएसआई) परिसर में 722 हरे पेड़ों की कटाई के मामले में केंद्र सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए संस्थान की निदेशक डॉ. सीमा परोहा को निलंबित कर दिया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में निलंबन आदेश जारी किया गया है।

➪ केंद्र सरकार का सख्त कदम, अरविंद कुमार रावत को सौंपा गया अतिरिक्त कार्यभार

जानकारी के अनुसार, एनएसआई परिसर में बड़ी संख्या में हरे पेड़ों की कटाई का मामला सामने आने के बाद इसकी जांच कराई गई थी। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मंत्रालय ने जिम्मेदारी तय करते हुए निदेशक डॉ. सीमा परोहा के खिलाफ कार्रवाई की है। पेड़ों की कटाई को लेकर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियमों के उल्लंघन के आरोप भी चर्चा में रहे हैं। मंत्रालय के आदेश के बाद डॉ. सीमा परोहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही संस्थान के प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित होने से बचाने के लिए अरविंद कुमार रावत को एनएसआई के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

यह मामला कानपुर में पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ था। पर्यावरण प्रेमियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई पर सवाल उठाए थे। अब केंद्र सरकार की इस कार्रवाई को मामले में जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के बाद संस्थान में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। साथ ही पूरे मामले में आगे की विभागीय प्रक्रिया और संभावित जांच पर भी नजर बनी हुई है।

भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं, अगले पांच दिन लू का प्रकोप

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। जिले में भीषण गर्मी का दौर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कृषि मौसम सेवा केंद्र और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आगामी पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन वर्षा की कोई संभावना नहीं है। साथ ही लू का प्रकोप भी जारी रहने के संकेत दिए गए हैं।

➪ कानपुर में तापमान सामान्य से ऊपर, मौसम विभाग ने किसानों और आमजन को सावधानी बरतने की सलाह दी

मंगलवार को अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम रहा। दिन के समय गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 65 प्रतिशत और न्यूनतम 33 प्रतिशत दर्ज की गई। हवा की औसत गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा रही तथा इसकी दिशा उत्तर-पश्चिम रही। बीते 24 घंटों में जिले में कोई वर्षा दर्ज नहीं की गई।

कृषि मौसम विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों में नमी संरक्षण के उपाय अपनाएं तथा सिंचाई कार्य सुबह या शाम के समय करें। लगातार बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए आमजन को भी दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है।

सड़क सुरक्षा उपकरणों के अभाव में बढ़ रहा हादसों का खतरा

शहरवासियों ने उठाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। महानगर में वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच सड़क सुरक्षा उपकरणों की कमी गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। शहर के कई प्रमुख मार्गों, फ्लाईओवरों, व्यस्त चौराहों तथा बाहरी क्षेत्रों की सड़कों पर आवश्यक सुरक्षा संकेतकों और उपकरणों का अभाव देखा जा रहा है। इसके कारण दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बढ़ रही है।

यातायात विशेषज्ञों के अनुसार सड़क सुरक्षा उपकरण केवल औपचारिकता नहीं बल्कि दुर्घटनाओं को रोकने का प्रभावी माध्यम हैं।

डिवाइडर रिफ्लेक्टर, कर्ब स्टोन रिफ्लेक्टर, रोड स्टड, डिलिनेटर, चेतावनी संकेतक बोर्ड और स्पष्ट रोड मार्किंग वाहन चालकों को सड़क की दिशा और स्थिति के बारे में सटीक जानकारी देते हैं।

विशेष रूप से रात, कोहरे और बारिश के दौरान इनकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शहर के कई हिस्सों में डिवाइडरों और तीखे मोड़ों पर पर्याप्त

रिफ्लेक्टिव सामग्री नहीं लगी है। वहीं, जहां सुरक्षा उपकरण लगाए गए थे, उनमें से कई क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और लंबे समय से उनका नवीनीकरण नहीं किया गया है। इससे वाहन चालकों को सड़क की दिशा समझने में कठिनाई होती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक सर्वे कर वहां आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाए जाने चाहिए। साथ ही उनकी नियमित जांच और रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने के साथ यातायात व्यवस्था अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बन सकेगी। शहरवासियों ने संबंधित विभागों से मांग की है कि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए खराब उपकरणों को तत्काल बदला जाए तथा प्रमुख मार्गों पर आवश्यक सुरक्षा संकेतकों की स्थापना की जाए, ताकि कानपुर की सड़कें आमजन के लिए अधिक सुरक्षित बन सकें।

रात में सबसे अधिक बढ़ता है जोखिम

विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश गंभीर सड़क हादसे रात के समय होते हैं। पर्याप्त रिफ्लेक्टर और रोड मार्किंग न होने से वाहन चालकों को मोड़, डिवाइडर और सड़क की सीमाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देतीं। ऐसे में तेज गति और कम दृश्यता दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ा देती है।

रखरखाव की अनदेखी भी बड़ी समस्या

सुरक्षा उपकरण लगाना ही पर्याप्त नहीं है। समय-समय पर उनकी मरम्मत और नवीनीकरण भी जरूरी है। क्षतिग्रस्त रिफ्लेक्टर, मिट चुकी रोड मार्किंग और टूटे संकेतक बोर्ड अपनी उपयोगिता खो देते हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है।

सुरक्षा के लिए सड़कों पर होने चाहिए ये प्रमुख उपकरण

डिवाइडर रिफ्लेक्टर, कर्ब स्टोन रिफ्लेक्टर, रोड स्टड (कैट्स आई), डिलिनेटर एवं गाइड पोस्ट, रिफ्लेक्टिव चेतावनी संकेतक बोर्ड, स्पीड लिमिट एवं दिशा सूचक बोर्ड, स्पष्ट रोड मार्किंग और जेब्रा क्रॉसिंग, ब्लिंकर लाइट एवं फ्लैशिंग सिग्नल, क्रैश बैरियर और गार्ड रेल, स्कूल, अस्पताल व संवेदनशील क्षेत्रों के चेतावनी संकेतक, सौर ऊर्जा चालित ट्रैफिक संकेतक, कोहरे वाले क्षेत्रों के लिए विशेष परावर्तक उपकरण

बांसमंडी चोरीकांड का खुलासा शातिर चोर गिरफ्तार, नकदी आईफोन और स्कूटी बरामद

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

» अनवरगंज पुलिस की कार्रवाई, गुप्त सूचना पर दबोचा गया आरोपी शहनवाज

कानपुर। कमिश्नरेट पुलिस ने बांसमंडी क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात का सफल खुलासा करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सेंट्रल जोन के डीसीपी और एसीपी के निर्देशन में अनवरगंज थाना प्रभारी के नेतृत्व में बांसमंडी चौकी प्रभारी राहुल शुक्ला एवं उनकी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की।पुलिस के अनुसार 22 और 23 मई की दरम्यानी रात बांसमंडी स्थित बेबीस कंपाउंड में चोरी की घटना हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय सूचनाओं तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने शहनवाज नामक आरोपी की तलाश तेज कर दी।गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने कालपी रोड स्थित कॉटन मिल गेट के सामने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक स्कूटी, तीन मोबाइल फोन, जिनमें एक आईफोन-12 भी शामिल है, एक पावर बैंक तथा 72 हजार 200 रुपये नकद बरामद किए गए।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके आपराधिक इतिहास के साथ अन्य संभावित वारदातों में संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। बरामद सामान को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस सफलता में अनवरगंज थाना पुलिस की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

काव्योत्सव में गूंजे पारिवारिक संवेदनाओं के स्वर, कविताओं ने बांधा समां

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। मां सरस्वती देवी स्मृति साहित्य संस्थान द्वारा आयोजित काव्योत्सव में कवियों और कवयित्रियों ने पारिवारिक संबंधों, मां, बेटी और गांव की स्मृतियों पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम में संवेदनाओं, संस्कृति और मानवीय रिश्तों की मिठास से सराबोर काव्यपाठ ने उपस्थित जनों की खूब सराहना बटोरी।काव्योत्सव की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि अशोक शास्त्री ने की, जबकि संचालन राजेश सिंह ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में राकेश राठौर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राजेन्द्र अवस्थी द्वारा सरस्वती वंदना से किया गया।कवयित्री शिवा प्रभारन ने अपनी रचना ÷साथ में चलती हवाएं भी जान लेती हैं मन की दशाएं, जुबां की मुस्कुराहट... प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। वरिष्ठ कवि अशोक शास्त्री ने मां पर आधारित मार्मिक रचना सुनाते हुए कहा, जाने कैसे पढ़ लेती थी मेरी गहन उदासी, इसी वजह से रह जाती थी उस दिन भूखी-प्यासी, जिस पर श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया।कवि राजेन्द्र अवस्थी ने अपनी लोकभाषा में रचित कविता ÷हम तो ढूंढ रहेन हैं गांव आपन ढूंढ हैं गांव के माध्यम से ग्रामीण जीवन की स्मृतियों और पुरानी जीवनशैली को जीवंत कर दिया। वहीं राजेश सिंह ने बेटी के महत्व पर आधारित रचना बेटी अगर नहीं होती तो यह संसार नहीं होता सुनाकर भावुक माहौल बना दिया।कवयित्री अनिता बृजेश ने मां को समर्पित अपनी रचना में कहा, माता है अनमोल खजाना सुनो जगत के प्यारे जन, मां के बिना सूना सारा जग, सूना है तन-मन-जीवन, जिसे श्रोताओं ने खूब सराहा। इसके अलावा अनुज मनमीत और शिव मूर्ति सिंह ने भी अपनी रचनाओं से काव्यधारा को आगे बढ़ाया।कार्यक्रम में शिवानी, शशि, नेहा, रोहित, दिनेश, अविरल, आन्या, आद्या और गुनगुन सहित अनेक साहित्यप्रेमी उपस्थित रहे। अंत में रमेश सिंह ने सभी आगंतुकों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

सम्पादकीय

जीवन से खिलवाड़ न कर पाएं घटिया उत्पाद

भारत में सामान्यतः उत्पादों पर गुणवत्ता व उपयोग-तिथि के दावों के बावजूद उसमें सामान के सेहत से जुड़े सरोकार सवालों के घेरे में रहे हैं। यह आम धारणा बनी हुई है कि कुछ लोग मुनाफे के लिए सामान की एक्सपाइरी डेट दर्ज करने में हेरफेर करने तक से नहीं चूकते। यह भी विश्वास से नहीं कहा जा सकता है कि सामान में शामिल घटकों का विवरण ईमानदारी से लेबल पर दर्ज किया गया हो। गाहे-बगाहे मीडिया व उपभोक्ता अदालतों में ऐसे मामलों की गूंज रहती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से संवेदनशील लोगों के जीवन पर सही लेबलिंग से आंच नहीं आ सकती। इसी के मद्देनजर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा कई खाद्य कंपनियों को गुमराह करने वाले ट्रेड नाम के इस्तेमाल और सेहत से जुड़े दावों के लिए नोटिस जारी करना, निश्चय ही एक स्वागतयोग्य कदम है। अक्सर प्रतिष्ठित उत्पाद वाली कंपनियों के लेबल लगाकर हल्के सामान बेचने के मामले भी उजागर होते हैं। हकीकत है कि आकर्षक पैकेजिंग के जरिये उत्पाद की न्यूट्रिशन से जुड़ी जानकारी को पार्श्व में डाल दिया जाता है। विडंबना यह है कि देश में ऐसा नियामक तंत्र विकसित नहीं हो पाया है जो लगातार जनहित में खाद्य उत्पादों की जांच-पड़ताल कर सके। निश्चित रूप से रेगुलेटरी संस्था की निगरानी सिर्फ कभी-कभार नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई कुछ समय के लिए तो सुर्खियां बनती हैं लेकिन फिर लोगों को इसकी याद कम ही रह जाती है। इस तरह की पहल को ग्राहकों की सुरक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और जागरूकता पर आधारित लगातार चलने वाले एक राष्ट्रीय मिशन का रूप दिया जा सकता है। निश्चित रूप से लाखों भारतीयों के लिए खाने की चीजों पर लेबलिंग सेहत से जुड़ा मामला है। मसलन कशेरुक रोग से पीड़ित लोग ग्लूटेन से बचने के लिए लेबलिंग पर लिखी जानकारी पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि यह उनकी आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है।निस्संदेह, कई एलर्जी व रोगों से जूझने वाले लोगों को कुछ उत्पादों में मौजूद पदार्थों की वजह से लंबे समय तक रहने वाली परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि उत्पादों के लेबल पर आधी-अधूरी, अस्पष्ट जानकारी ही दी जाती है। अक्सर उत्पादों पर हेल्दी, नेचुरल और आयुर्वेद पद्धति पर आधारित जैसे लुभावने शब्दों का इस्तेमाल करके ग्राहकों को भ्रमित किया जाता है, जिससे उपभोक्ता असमंजस की स्थिति में पड़ आते हैं। मधुमेह, एलर्जी और खानपान से जुड़े दूसरे परहेजों में अस्पष्ट व गलत जानकारी हानिकारक हो सकती है। उत्पादकों की ईमानदारी व उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर भरोसा करना ग्राहकों के लिए मुश्किल हो जाता है।

जैसे-जैसे भारतीय समाज में पैकेट बंद खाद्य पदार्थों का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, देश में एक मजबूत नियामक ढांचे की सख्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। दरअसल, देखने में आता है कि छोटे दुकानदार अपने नुकसान को बचाने के लिए उसका बोझ ग्राहकों पर डाल देते हैं। एक प्रतिबद्ध नैतिकता का अभाव इस मुनाफे के कारोबार में अक्सर नजर आता है। निस्संदेह, किसी उत्पाद के पैकेट में उल्लेखित जानकारी ग्राहक के समझने के लिए आसान होनी चाहिए। साथ ही बिना तथ्य व तार्किकता के सेहत से जुड़े दावे करने वाले उत्पादकों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।

इसके लिये जरूरी है कि समय-समय पर इन उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया की औचक निगरानी व पड़ताल होनी चाहिए। साथ ही बार-बार नियम तोड़ने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान भी होना जरूरी है। देश में कोशिश हो कि उपभोक्ता जागरूकता अभियान को सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का हिस्सा बनाया जाए। इस अभियान में स्कूलों, हेल्थकेयर संस्थानों और विभिन्न मीडिया समूहों को आम लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए कि किसी उत्पाद में दर्ज न्यूट्रिशन लेबल को कैसे समझें। कैसे भ्रमित करने वाले दावों की पड़ताल करें।

साथ ही कैसे वे सेहत के अनुकूल उत्पादों के विकल्प का चयन कर सकें। निश्चित रूप से एक जागरूक उपभोक्ता ही अनैतिक मार्केटिंग के खिलाफ बचाव की राह दिखा सकता है।

एसआईआर की तार्किकता और विरोध का प्रश्न

के.एस तोमर

हालांकि, एसआईआर नागरिकता की परीक्षा नहीं है, लेकिन इसके मार्फत 'नागरिकता की सीमित जांच' का आधार बना सकता है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने के बाद से एक वर्ग के मन में संशय है। खबरें हैं कि बिहार और.हालांकि, एसआईआर नागरिकता की परीक्षा नहीं है, लेकिन इसके मार्फत 'नागरिकता की सीमित जांच' का आधार बना सकता है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने के बाद से एक वर्ग के मन में संशय है। खबरें हैं कि बिहार और बंगाल की नई सरकारों ने घोषणा की है कि मतदाता सूची से जिनके नाम कट गए हैं, उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे।

हाल ही में 'इंडिया' गठबंधन ने पांच-सूत्री प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एक यह भी है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा। यह गठबंधन 'एसआईआर' को 'वोट चोरी' मानता है। इसके कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 'एसआईआर' को लेकर चुनाव-आयोग को क्लीन-चिट दी है। प्रश्न है कि ऐसे में पत्र लिखने से मिलेगा क्या? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का कहना है, हम इसे 'वोट लूट' की कोशिश मानते हैं। भारत में घुसपैठ और नागरिकता रजिस्टर पिछले कई दशकों से बहस में हैं। यह बहस अब मतदाता सूची की बहस के साथ जुड़ गई है। 'एसआईआर' के देश में दो दौर हो चुके हैं और तीसरा शुरू हो गया है। पहला दौर मुख्यतः बिहार-केंद्रित था, जो जून से सितंबर, 2025 तक चला। 27 अक्तूबर से दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत, नौ राज्य और तीन केंद्र-शासित क्षेत्र शामिल थे।गत 14 मई को निर्वाचन आयोग ने 'एसआईआर' के तीसरे दौर की भी घोषणा कर दी, जिसमें सोलह राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों को कवर किया गया है। इसके पूरा होने के बाद जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके साथ इस प्रक्रिया को बहस नए सिरे से शुरू होगी, जिसकी अनुगूंज संसद के मॉनसून सत्र में सुनाई पड़ेगी।शिकायतें पहले दौर के पहले से ही शुरू हो गई थीं, पर पश्चिम बंगाल का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गया। इस दौर में करीब 27 लाख वोटरों ने अपने नाम कटने को चुनौती दी। वे विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाए, क्योंकि उनकी सुनवाई के लिए नियुक्त न्यायाधिकरण इस काम को पूरा नहीं कर पाए। यह काम चुनाव परिणाम आने के बाद भी चल ही रहा है। इन 27 लाख में 60 प्रतिशत से ज्यादा वोटरों की सूची में वापसी हो चुकी है और अंतिम समाचार मिलने तक न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया जारी है। सवाल है कि उनकी सुनवाई के लिए नागरिक-प्रशासन पर राज्य सरकार ने भरोसा क्यों नहीं किया? चुनाव-आयोग की व्यवस्था है कि 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' के कारण कोई नाम 'अनमैप्ड' रह जाए, तो एक सूची में वर्णित दस्तावेज़ों में से कोई एक देकर अपने नाम को बनाए रखा जा सकता है।

पर बंगाल में अविश्वास इतना गहरा था कि उस रास्ते पर जाने के बजाय लंबे रास्ते को अपनाया गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं दे पाए।कई तरह के सवाल सभी पक्षों से हैं। आयोग ने सूची के गहन-संशोधन के लिए पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया? 2002 और 2003 की मतदाता सूचियों तक पहुंच पाना आसान काम नहीं है। पुरानी सूचियां जिस तरीके से बनाई गई हैं, उनमें नाम, पते और वोटर कार्ड की संख्या खोजना खासा मुश्किल काम है।

सामान्य नागरिक कागज-पत्रों के आदी नहीं हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया आसान नहीं है।देश की आम जनता दस्तावेजों की अभ्यस्त नहीं है।

'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' को दूर करने के लिए दस्तावेज़ों को भी आसान बनाने की ज़रूरत है। वोटर को पुरानी सूची में अपना नाम खोजने में दिक्कत होती है। उसकी मदद की जानी चाहिए। आयोग की वेबसाइट को सरल बनाने और इस काम को करने वाले बीएलओ को बेहतर तरीके से तैयार करने की ज़रूरत भी है।

विरोधी नारे वाला दल क्यों बना तृणमूल के बागियों का नया ठिकाना

गुमनाम पार्टी में क्यों शामिल हुए ज्यादा के नामी सांसद? दलबदल विरोधी नारे वाला दल क्यों बना तृणमूल के बागियों का नया ठिकानासबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस एनसीपीआई में यह विलय हुआ है, उसका अब तक का राजनीतिक अस्तित्व लगभग नगण्य रहा है। 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में इस दल ने चार उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन आखिरकार तीन सीटों पर ही चुनाव लड़ पाया।तृणमूल कांग्रेस में उठी बगावत ने राष्ट्रीय राजनीति को ऐसा मोड़ दे दिया है जिसकी गूंज आने वाले महीनों तक सुनाई दे सकती है।

हम आपको बता दें कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने अचानक एक लगभग गुमनाम दल नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय का ऐलान कर दिया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अलग समूह के तौर पर मान्यता तथा सदन में अलग बैठने की मांग कर डाली। इस घटनाक्रम ने केवल बंगाल की राजनीति को नहीं हिलाया, बल्कि दलबदल कानून, विपक्ष की एकजुटता और संसद की शक्ति संतुलन की बहस को भी फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है।सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस एनसीपीआई में यह विलय हुआ है, उसका अब तक का राजनीतिक अस्तित्व लगभग नगण्य रहा है। 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में इस दल ने चार उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन आखिरकार तीन सीटों पर ही चुनाव लड़ पाया। पार्टी के उम्मीदवारों का प्रदर्शन इतना कमजोर रहा कि वे कई जगह नोटा से थोड़ा ही आगे निकल सके। त्रिपुरा की चावमनु सीट पर पार्टी उम्मीदवार बरजेदा त्रिपुरा को केवल 536 वोट मिले, जबकि नोटा को 500 वोट प्राप्त हुए। कैलाशहर सीट पर पार्टी को मात्र 286 वोट मिले। कुल मिलाकर दो सीटों पर एनसीपीआई को सिर्फ 822 वोट हासिल हुए थे।खास बात यह भी है कि इस पार्टी का चुनाव चिह्न 'पेन की

निब' है और इसने नारा दिया था, ÷अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलबदलुओं को नकारें।÷ लेकिन राजनीति की विडंबना देखिए कि अब वही दल देश के सबसे चर्चित दलबदल का मंच बन गया है। वैसे इस पूरे घटनाक्रम के पीछे केवल नाराजगी नहीं, बल्कि गहरी राजनीतिक रणनीति दिखाई दे रही है। बागी सांसदों का मकसद सीधे भाजपा में जाना नहीं, बल्कि पहले एक अलग राजनीतिक पहचान बनाकर दलबदल कानून से बचना माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत यदि किसी दल के दो तिहाई विधायक या सांसद किसी दूसरे दल में विलय करते हैं, तो उन्हें अयोग्यता से राहत मिल सकती है। इसी कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए बागी गुट खुद को ÷असली तृणमूल÷ साबित करने की जमीन तैयार कर रहा है।तृणमूल के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने साफ कहा है कि अभी उन्होंने एनसीपीआई में विलय किया है, लेकिन संसद का अगला सत्र शुरू होने पर वह तृणमूल नाम और पहचान पर दावा करेंगे। उनका कहना है कि दो तिहाई सांसद उनके साथ हैं, इसलिए वास्तविक राजनीतिक अधिकार भी उसी गुट के पास होना चाहिए। दूसरी ओर, टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र राजनीतिक संकट वाले फैसले का हवाला देते हुए कहा कि केवल विधायी दल का टूटना पर्याप्त नहीं होता, मूल राजनीतिक दल का विलय भी जरूरी है।देखा जाये तो यही वह बिंदु है जहां यह लड़ाई केवल संख्या की नहीं, बल्कि कानूनी और संवैधानिक व्याख्या की बन जाती है। तृणमूल कांग्रेस का तर्क है कि पार्टी सर्वोपरि है, सांसद नहीं। जबकि बागी गुट संख्या बल के आधार पर वैधता चाहता है। इस टकराव का अंतिम फैसला अब अदालत और लोकसभा अध्यक्ष की व्याख्या पर निर्भर करेगा।हम आपको यह भी बता दें कि इस घटनाक्रम की तुलना 2016 के अरुणाचल प्रदेश संकट से भी की जा रही है। तब कांग्रेस के अधिकांश विधायक पहले पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में गए और बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। उसी रास्ते ने भाजपा को पूर्वोत्तर में पहली पूर्ण सरकार दी थी। अब तृणमूल के भीतर भी वैसी ही पटकथा दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दांव बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी शक्ति पर लगा है।राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह ममता बनर्जी के नेतृत्व के लिए सबसे बड़ा झटका माना जाएगा।

सिल्ट निकासी कार्य बना किसानों के लिए मुसीबत, पटरी कटने से खेतों में भरा पानी

शिवराजपुर क्षेत्र में रजबहा की पटरी क्षतिग्रस्त होने का लगाया आरोप

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। शिवराजपुर थाना क्षेत्र में रजबहा और नहर की पटरी से सिल्ट निकासी का कार्य किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। किसानों का आरोप है कि कार्य के दौरान विभागीय मानकों की अनदेखी करते हुए जरूरत से अधिक गहराई तक खुदाई कर दी गई, जिससे रजबहा की पटरी कट गई और पानी आसपास के खेतों में फैल गया। इस घटना से रौतापुर सहित कई गांवों के किसानों में नाराजगी है।

ग्रामीणों के अनुसार सिल्ट निकासी के नाम पर की गई खुदाई से रजबहा की संरचना कमजोर हो गई। इसके चलते पानी का बहाव नियंत्रित नहीं रह सका और कई खेतों में जलभराव की स्थिति बन गई। किसानों का कहना है कि धान और अन्य खरीफ फसलों की तैयारी के बीच खेतों में पानी भरने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रभावित किसानों ने मौके पर पहुंचकर कार्य का विरोध किया और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई।

किसानों का आरोप है कि शिकायत करने के दौरान ठेकेदार पक्ष से जुड़े कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया। विरोध बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में धक्का-मुक्की और मारपीट में बदल गई। किसानों का दावा है कि कुछ लोगों ने डंडों से हमला किया और जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया और ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सिल्ट निकासी का कार्य तकनीकी मानकों के अनुसार कराया जाता तो पटरी क्षतिग्रस्त नहीं होती और खेतों में पानी भरने जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होती। किसानों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

सिंचाई विभाग के अवर अभियंता रूद्र सिंह ने बताया कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हो गई है। विभागीय स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है और मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिवराजपुर थाना प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है। सभी तथ्यों की जांच कराई जा रही है तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तकनीकी मानकों पर सवाल:
सिल्ट निकासी का उद्देश्य नहरों और रजबहों की जल वहन क्षमता बढ़ाना होता है। यदि खुदाई निर्धारित गहराई और चौड़ाई से अधिक कर दी जाए तो पटरी कमजोर होकर कट सकती है। किसानों की शिकायत इसी तकनीकी लापरवाही की ओर इशारा कर रही है।

फसलों पर पड़ सकता है असर

खेतों में अचानक जलभराव होने से खरीफ सीजन की तैयारियां प्रभावित हो सकती हैं। लंबे समय तक पानी भरा रहने पर मिट्टी की गुणवत्ता और फसल उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है, जिससे किसानों की लागत बढ़ सकती है।

जांच के बाद तय होगी जिम्मेदारी

मामले में सिंचाई विभाग और पुलिस दोनों स्तरों पर जांच शुरू हो चुकी है। यदि पटरी कटने और मारपीट के आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित ठेकेदार, जिम्मेदार कर्मियों अथवा अन्य आरोपितों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई संभव है।

अरौल-मकनपुर स्टेशन के पास फुट ओवरब्रिज निर्माण शुरू, लोगों को मिलेगी राहत

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। अरौल-मकनपुर रेलवे स्टेशन के निकट जीटी रोड पार करने में लोगों को होने वाली परेशानी जल्द ही दूर होने वाली है। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद यहां फुट ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई है।

स्टेशन के आसपास प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों और ग्रामीणों का आवागमन रहता है। जीटी रोड पर लगातार बढ़ते यातायात के कारण सड़क पार करना जोखिम भरा साबित हो रहा था। ऐसे में स्थानीय लोग सुरक्षित आवागमन के लिए फुट ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग उठा रहे थे। जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इस संबंध में लगातार प्रयास किए गए, जिसके बाद निर्माण कार्य को मंजूरी मिली। फुट ओवरब्रिज तैयार होने के बाद रेलवे यात्रियों के साथ-साथ आसपास के गांवों के लोगों को भी काफी राहत मिलेगी तथा सड़क पार करते समय दुर्घटना की आशंका कम होगी। निर्माण कार्य शुरू होने की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय लोगों ने संतोष व्यक्त करते हुए इसे जनहित का महत्वपूर्ण कदम बताया है।

➪ **जीटी रोड पार करने में होगी आसानी, यात्रियों और ग्रामीणों को मिलेगा सुरक्षित रास्ता**

कमरे में फंदे से लटका मिला किसान का शव

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। अरौल थाना क्षेत्र के आंकिन गांव में सोमवार रात एक किसान का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

गांव निवासी 45 वर्षीय सुरेश कुशवाहा अविवाहित थे और खेती-किसानी कर जीवन यापन करते थे। बताया गया कि सोमवार शाम उन्होंने घर के कमरे में पंखे के कुंडे से रस्सी के सहारे फंदा लगा लिया। कुछ देर बाद किसी काम से घर पहुंचे उनके भतीजे ने उन्हें फंदे पर लटका देखा। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। आनन-फानन में उन्हें नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

➪ **घर पहुंचे उनके भतीजे ने फंदे पर लटका देखा**

घटना की जानकारी मिलते ही अरौल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए। ग्रामीणों के अनुसार मृतक को शराब पीने की लत थी।

हालांकि आत्मघाती कदम उठाने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। थाना प्रभारी विनय तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जनसंपर्क अभियान तेज

पत्रिका भेंट कर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत बिल्हौर विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने क्षेत्र की जनता एवं उद्यमियों से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, ऐतिहासिक निर्णयों और विकास कार्यों से संबंधित पत्रिका भेंट कर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी।

विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने कहा कि बीते 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण, आधारभूत विकास, महिला सशक्तीकरण तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अभियान के दौरान उन्होंने लोगों से संवाद कर उनके सुझाव भी प्राप्त किए। इस दौरान उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

युवक की मौत पर आगरा में बवाल पुलिस पर पथराव, कई जवान घायल

» हादसे के बाद शव रखकर लगाया जाम, कार सवारों को भगाने का आरोप

उग्र भीड़ ने आधा किलोमीटर तक पुलिस को दौड़ाया, लाठीचार्ज के बाद हालात काबू में

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

आगरा। आगरा के फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग पर सोमवार को हुए एक सड़क हादसे ने हिंसक रूप ले लिया। पूठपुरा गांव के पास थार वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। हादसे में शामिल थार पर पुलिस का स्टीकर लगा होने के कारण लोगों ने पुलिस पर वाहन सवारों को मौके से भगाने का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच टकराव हो गया, जिसके बाद पथराव और लाठीचार्ज की नौबत आ गई।

जानकारी के अनुसार, दयालबाग क्षेत्र के खासपुर बाहदरपुर निवासी 22 वर्षीय मनीष अपनी ससुराल फिरोजाबाद के बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र से फतेहाबाद लौट रहा था। पूठपुरा गांव के पास एक थार और ट्रैक्टर की टक्कर के दौरान थार उसकी बाइक से भी जा भिड़ी।

हादसे में मनीष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, स्कूटी सवार तीन अन्य लोग भी घायल हो गए।टक्कर के बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा, जबकि उसमें सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई।युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने लगी तो ग्रामीणों ने विरोध करते हुए शव एंबुलेंस से उतार लिया। हालात बिगड़ते देख आसपास के कई थानों का अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने हादसे में शामिल थार को आग के हवाले करने की बात कही। इसी बीच पुलिस अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया।पथराव इतना तीव्र था कि पुलिसकर्मियों को पीछे हटना पड़ा।

उग्र भीड़ ने पुलिस को करीब आधा किलोमीटर तक दौड़ाया। घटना में दस से अधिक पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। कई जवानों को सिर और सीने में चोटें आईं, जबकि कुछ की वर्दियां भी फट गईं। पुलिस कमिश्नरेट का एक वाहन भी पथराव में क्षतिग्रस्त हो गया।स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया।इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने घटनास्थल से तीन लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि उपद्रव और पथराव में शामिल अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है।

लखनऊ में थी ट्रेन पलटने की साजिश, कई लोग हिरासत में

रेल मंत्रालय ने लिया संज्ञान, जीआरपी-आरपीएफ ने घटनास्थल पर घंटों की पड़ताल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ के दिलकुशा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर भारी लोहे का एंगल रखकर पंजाब मेल को दुर्घटनाग्रस्त करने की कथित साजिश के मामले ने रेलवे और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। घटना का संज्ञान रेल मंत्रालय ने भी लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को जीआरपी और आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और कई घंटे तक गहन जांच-पड़ताल की। जांच के दौरान अधिकारियों ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया। रेलवे ट्रैक के किनारे कई किलोमीटर तक पैदल तलाशी ली गई और ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई।

प्रारंभिक जांच में अधिकारियों का मानना है कि ट्रैक पर रखा गया लोहे का एंगल या गेटनुमा ढांचा करीब 50 किलोग्राम वजनी था, जिसे वहां तक पहुंचाने और पटरी पर रखने में कम से कम तीन से चार लोगों की भूमिका रही होगी।एसपी जीआरपी रोहित मिश्रा और आरपीएफ कमांडेंट देवांश शुक्ला ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों के अनुसार, घटनास्थल तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन है। आसपास घना जंगल, सेना का प्रतिबंधित क्षेत्र और सीमित आवागमन वाले रास्ते हैं। ऐसे में किसी एक व्यक्ति द्वारा इतना भारी लोहे का ढांचा वहां तक ले जाना लगभग असंभव प्रतीत होता है।जांच एजेंसियों ने घटनास्थल तक पहुंचने वाले मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है, लेकिन अब तक कोई संदिग्ध व्यक्ति स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ लोगों की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई हैं, जिनकी पहचान और सत्यापन का काम जारी है।

पुलिस ने मामले की जांच के तहत कई संदिग्ध कबाड़ियों और चोरी के मामलों में शामिल रहे लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। जांच एजेंसियां इस संभावना पर भी काम कर रही हैं कि किसी कबाड़ी या नशे के आदी व्यक्ति ने लोहे के ढांचे को काटने या बेचने के उद्देश्य से ट्रैक पर रखा हो। हालांकि अब तक पूछताछ में कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी है।गौरतलब है कि शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे रेलवे ट्रैक पर रखा यह भारी लोहे का एंगल पंजाब मेल के लोको पायलट की सतर्कता से बड़ी दुर्घटना में बदलने से बच गया था। लोको पायलट ने समय रहते आपात ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी थी, हालांकि एंगल इंजन में फंस गया था। घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने इसे गंभीर सुरक्षा खतरा मानते हुए जांच शुरू कराई थी।इस संबंध में वरिष्ठ खंड अभियंता (रेलपथ) राज किशोर मिश्रा की तहरीर पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही हैं और साजिश के पीछे शामिल लोगों की तलाश में जुटी हैं।

ग्राम विकास अधिकारी मौत प्रकरण में बड़ा एक्शन, दो प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि पर एफआईआर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

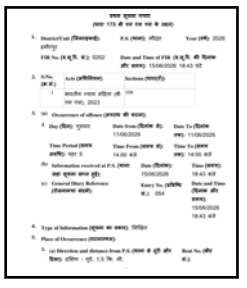

हमीरपुर। हमीरपुर जिले में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) राजू सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो ग्राम प्रधानों और एक प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह कार्रवाई मृतक के परिजनों की तहरीर और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई है।

जानकारी के अनुसार, मौदहा विकासखंड में तैनात ग्राम विकास अधिकारी राजू सिंह का शव कुछ दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला था। घटना के बाद से ही परिजन इसे आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बताते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की थी। परिजनों का आरोप है कि राजू सिंह ने मौत से पहले अपनी पत्नी से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों से अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी। आरोप है कि वह लगातार मानसिक दबाव में थे और इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया।

पुलिस ने जांच के बाद कुनहेटा ग्राम प्रधान रामराज, हिमौली ग्राम प्रधान सुनील तथा प्रधान प्रतिनिधि जुम्मन खान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है और क्षेत्र में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, मृतक के परिजन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव गिरफ्तार

» विजिलेंस ने जांच का दायरा बढ़ाया, पत्नी, करीबी सहयोगियों और एनआरएचएम ठेकों से जुड़े लोगों से होगी पूछताछ

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस विभाग ने जांच का दायरा और व्यापक कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार मुकेश श्रीवास्तव की संपत्तियों, वित्तीय लेन-देन तथा उनसे जुड़े व्यक्तियों की भूमिका की गहन पड़ताल की जा रही है।

जांच एजेंसियां उनकी पत्नी पूजा श्रीवास्तव सहित कई करीबी सहयोगियों से पूछताछ की तैयारी कर रही हैं। विजिलेंस ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही गबन से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों की भी जांच तेज कर दी गई है।

सूत्रों के अनुसार आरपी कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिले विभिन्न सरकारी ठेकों की फाइलें खंगाली जा रही हैं।

इसके अलावा सृष्टि एंटरप्राइजेज और बीएल एंटरप्राइजेज को आवंटित टेंडरों की भी जांच की जाएगी। अधिकारियों को टेंडर प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की आशंका है।विजिलेंस की टीम श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में हुए कार्यों का रिकॉर्ड भी जुटा रही है। संबंधित अवधि में तैनात रहे तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे।

जांच का प्रमुख फोकस राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) से जुड़े ठेकों और टेंडरों पर है।अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय दस्तावेजों, बैंक खातों, भुगतान रिकॉर्ड और ठेका आवंटन प्रक्रिया की विस्तृत जांच की जा रही है। यदि जांच में अन्य व्यक्तियों की भूमिका सामने आती है तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। विजिलेंस का दावा है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष और तथ्यपरक जांच की जाएगी तथा दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

करसा गांव में युवती के छिपे होने की सूचना पर बजरंग दल सक्रिय, पुलिस पहुंचने से पहले संदिग्ध फरार

» धर्म परिवर्तन की आशंका के बीच परिजनों की गुहार, बजरंग दल और पुलिस ने की संयुक्त तलाश

नामजद युवक पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, युवती की तलाश में तेज हुई कार्रवाई

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। घाटमपुर रेउना थाना क्षेत्र के झबैया अकबरपुर गाव में एक 22 वर्षीय युवती के लापता होने और धर्म परिवर्तन की आशंका से जुड़े मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों की शिकायत के बाद जहां पुलिस जांच में जुटी है, वहीं बजरंग दल ने भी पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सक्रिय भूमिका निभाई। रविवार को करसा गांव में युवती के छिपे होने की सूचना मिलने पर बजरंग दल के पदाधिकारियों और पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश दी, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही संदिग्ध युवक मौके से फरार हो गया।

वही पीड़ित पिता द्वारा पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि उनकी 22 वर्षीय पुत्री 4 जून को घर से निकली थी और उसके बाद वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजनों का आरोप है कि गांव का एक नामजद युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है तथा उसके माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने की भी आशंका है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से युवती की सकुशल बरामदगी और आरोपित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

मामले की जानकारी मिलते ही कानपुर नगर के बजरंग दल विभाग सह संयोजक शुभम सौर्य तथा कानपुर देहात के जिला सह संयोजक हिमांशु परिहार अपनी टीम के साथ सक्रिय हो गए। करसा गांव में युवती के छिपे होने की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तत्काल रेउना पुलिस को अवगत कराया। इसके बाद पुलिस और बजरंग दल की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही संदिग्ध युवक वहां से फरार हो गया। इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में भी तलाश अभियान चलाया गया।

बजरंग दल पदाधिकारियों ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी प्रकार के दबाव, प्रलोभन या अवैध गतिविधि के प्रमाण मिलते हैं तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। युवती की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल इस प्रकरण को लेकर इलाके में चर्चाओं का दौर जारी है और स्थानीय लोग भी युवती की सकुशल बरामदगी की उम्मीद लगाए हुए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मामले से जुड़ी कोई भी ठोस जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करें, ताकि जांच को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।

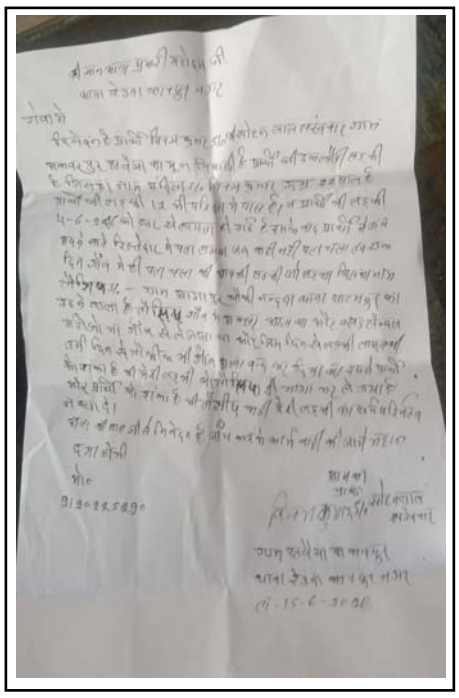

भाई-भाई के विवाद में मारपीट, युवक का सिर फटा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। मऊ गांव निवासी रूप सिंह ने भोगनीपुर कोतवाली में दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसका भाई रज्जन उसके साथ गाली-गलौज कर रहा था।

जब उसने इसका विरोध किया तो रज्जन ने डंडे से उस पर हमला कर दिया। डंडा उसके सिर पर लगने से वह घायल हो गया और उसका सिर फट गया। रूप सिंह का आरोप है कि घटना के दौरान बीचबचाव करने पहुंची उसकी पत्नी बबीता के साथ भी रज्जन ने मारपीट की। भोगनीपुर कोतवाली के उपनिरीक्षक राजेन्द्र कुमार रंजन ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया है।

शराब पीने से मना करने पर चाचा पर किया हमला

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के बहेरी कला गांव निवासी वीरेंद्र कटियार ने भोगनीपुर कोतवाली में दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उनका भतीजा अभिनाश घर के पास शराब पी रहा था। उन्होंने उसे शराब पीने से मना किया तो वह आगबबूला हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान अभिनाश ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी गर्दन पर चोट लग गई। घटना के बाद परिजनों ने घायल वीरेंद्र को उपचार दिलाया। वहीं, पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। भोगनीपुर कोतवाली के उपनिरीक्षक राजेन्द्र कुमार रंजन ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है।

एक साल बाद भी नहीं बनी सड़क गड्ढों में चलने को मजबूर ग्रामीण

» 2025 में आदेश के बावजूद सचिव ने नहीं कराया निर्माण, आईजीआरएस निस्तारण पर उठे सवाल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। गजनेर क्षेत्र के ग्राम कटेढ़ी में सड़क निर्माण को लेकर प्रशासनिक आदेशों के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। वर्ष 2025 में आईजीआरएस शिकायत पर संबंधित अधिकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त आरसीसी मार्ग को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। इससे ग्रामीण आज भी गड्ढों और उबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के निस्तारण में मरम्मत और निर्माण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ग्राम सचिव की उदासीनता के चलते आदेश सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया। बरसात के दिनों में सड़क की स्थिति और भी खराब हो जाती है,

जिससे पैदल चलने वाले, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और दोपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी और ग्राम सचिव निर्माण कार्य को लेकर गंभीर नहीं हैं, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आईजीआरएस पर दिए गए आदेशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कराया जाए, ताकि लोगों को गड्ढों भरे रास्ते से राहत मिल सके।

निराला नगर प्रीमियर लीग के फाइनल में बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

पूर्व विधायक कमलेश चंद्र दिवाकर ने मैदान में बल्लेबाजी की

रसूलाबाद (कानपुर देहात)। निराला नगर वार्ड में आयोजित निराला नगर प्रीमियर लीग-2026 के फाइनल मुकाबले में भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।नगर पंचायत रसूलाबाद के निराला नगर वार्ड में आयोजित इस टूर्नामेंट के अंतिम दिन खिलाड़ियों और दर्शकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। पूर्व विधायक कमलेश चंद्र दिवाकर ने मैदान में बल्लेबाजी कर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि आज अनेक युवा खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।

टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कमला क्लब माधव नगर और रतनपुर की टीमों के बीच खेला गया। मैच के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और रोमांचक मुकाबले का आनंद लिया। कार्यक्रम में आयोजक विवेक पाल, संजय चौहान, प्रधान सत्यप्रकाश कठेरिया, प्रीत पाल, गोपी सेंगर, आदित्य राना, भानु प्रताप सिंह, सभासद शिवकुमार प्रजापति, आशीष पाल, शिवजी तिवारी, रामजी तिवारी, रामआसरे राजपूत, पप्पू दिवाकर, पूर्व सभासद शीलू पाल, शिवा ठाकुर, अंकित पाल आदि उपस्थित रहे।

यमुना में डूबे किशोर व किशोरी के शव एक किलोमीटर दूर मिले

» एसडीआरएफ ने मूसानगर के पक्का घाट के पास से बरामद किए शव

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। मूसानगर थाना क्षेत्र के नयापुरवा गांव के पास यमुना नदी में डूबे किशोर और किशोरी के शव सुबह घटना स्थल से करीब एक किलोमीटर दूर मूसानगर के पक्का घाट के पास बरामद कर लिए गए। एसडीआरएफ टीम ने पहले किशोर और करीब 15 मिनट बाद किशोरी का शव नदी से बाहर निकाला। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।जानकारी के अनुसार, नयापुरवा निवासी सुनील निषाद की 12 वर्षीय पुत्री जाह्नवी उर्फ भूरी रविवार सुबह पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली, 15 वर्षीय ज्योति पुत्री अनिल के साथ यमुना नदी में नहाने गई थी। नहाने के दौरान दोनों गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं।मौके पर मौजूद गांव के 16 वर्षीय अनंतराम ने साहस दिखाते हुए ज्योति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन जाह्नवी को बचाने के प्रयास में वह स्वयं गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय गोताखोरों ने दोनों की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को बुलाया। सुबह एसडीआरएफ की टीम ने घटना स्थल से करीब एक किलोमीटर दूर मूसानगर के पक्का घाट के पास से करीब सात बजे अनंतराम का शव बरामद किया। इसके लगभग 15 मिनट बाद जाह्नवी का शव भी नदी से बाहर निकाल लिया गया। मूसानगर थाना प्रभारी अमिता वर्मा ने बताया कि यमुना में डूबे दोनों शव बरामद कर लिए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अवैध खनन पर पुलिस की कार्रवाई, दो ट्रैक्टर जब्त

» खनन कार्य में लगे तीन लोगों को हिरासत में लिया गया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र के कई गांवों में शाम ढलते ही खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं और जेसीबी व ट्रैक्टरों की मदद से मिट्टी का अवैध खनन किया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार, चांदापुर, सुखसौरा, नोनापुर, अस्तिया, कुसरजापुर, बहेरी और मूसानगर थाना के सिगरसीपुर आदि सहित दर्जनों गांवों में लंबे समय से अवैध खनन का खेल चल रहा है। आरोप है कि कुछ खनन संचालकों ने औपचारिकता पूरी करने के लिए एक गांव के नाम से अनुमति संबंधी फाइलें बनवा रखी हैं, जबकि खनन दूसरे स्थानों पर किया जा रहा है।

इसी क्रम में रात भोगनीपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो ट्रैक्टर और एक ट्रैक्टर में बंधे सूपड़े को जब्त किया। कोतवाली के उपनिरीक्षक वीरपाल ने बताया कि वह पुलिस बल के साथ रात्रि गश्त पर थे। गश्त के दौरान अकोढ़ी गांव के समीप एक ट्रैक्टर में बंधे सूपड़े से मिट्टी का खनन होता दिखाई दिया। सूचना की पुष्टि होने पर पुलिस ने मौके पर छापेमारी की और खनन कार्य में लगे तीन लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौके से खनन की गई मिट्टी से लदे दो ट्रैक्टर तथा एक ट्रैक्टर में बंधे सूपड़े को कब्जे में लेकर खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई की। जब्त वाहनों को कोतवाली परिसर में खड़ा कराया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और संबंधित विभाग को भी सूचना दे दी गई है। क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

मॉर्निंग रेड छह बिजली चोर दबोचे गए

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने सुबह अकोढ़ी एवं पुखरायां उपकेंद्र क्षेत्रों में मॉर्निंग रेड अभियान चलाकर बिजली चोरी और निर्धारित भार से अधिक विद्युत उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की।

विजिलेंस प्रभारी वंदना शुक्ला के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में टीम ने कुल छह उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की। विजिलेंस टीम के अवर अभियंता तापस रंजन ने बताया कि जांच के दौरान दो उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली चोरी करते पाए गए, जिनके खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

इसके अलावा चार ऐसे उपभोक्ता भी चिन्हित किए गए, जिन्होंने एक किलोवाट क्षमता का कनेक्शन ले रखा था, लेकिन उनके परिसर में पांच से सात किलोवाट तक का विद्युत भार संचालित पाया गया। विभाग ने ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त भार का आकलन किया है। अवर अभियंता तापस रंजन ने बताया कि बिजली चोरी और अनियमित विद्युत उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे निर्धारित क्षमता के अनुसार ही बिजली का उपयोग करें तथा आवश्यकता होने पर अपने कनेक्शन का भार बढ़वाएं। अभियान के दौरान अकोढ़ी उपकेंद्र के अवर अभियंता अंकित सचान, हेड कांस्टेबल सर्वेश सिंह सहित बिजली विभाग और विजिलेंस टीम के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

विद्यालय खुले, छात्र रहे नदारद अभिलेखीय कार्यों में जुटे रहे शिक्षक

» नए शैक्षिक सत्र के तहत 16 जून से विद्यालय पुनः संचालित होने लगे

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रसूलाबाद (कानपुर देहात)। शासन के निर्देशानुसार परिषदीय विद्यालयों में मंगलवार से नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो गई। हालांकि, पहले ही दिन अधिकांश विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बेहद कम रही। बच्चों के विद्यालय न पहुंचने के कारण शिक्षक पूरे दिन अभिलेखीय कार्यों, नामांकन संबंधी तैयारियों और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे रहे।

गौरतलब है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 19 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था। नए शैक्षिक सत्र के तहत 16 जून से विद्यालय पुनः संचालित होने लगे हैं। विद्यालय खुलने के साथ ही शिक्षकों ने परिसर की साफ-सफाई, कक्षाओं की व्यवस्था, नामांकन रजिस्टरों के अद्यतन और अन्य प्रशासनिक कार्यों का जायजा लिया। शिक्षकों का कहना है कि अभिभावकों में अब भी यह धारणा बनी हुई है कि विद्यालयों में नियमित पढ़ाई जुलाई माह से शुरू होती है, जिसके चलते पहले दिन छात्रों की उपस्थिति नहीं रही। इस संबंध में निराला नगर स्थित कंपोजिट विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका प्रियंका दीक्षित ने बताया कि छात्र संख्या बढ़ाने और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षक गांव-गांव और घर-घर जाकर अभिभावकों से संपर्क करेंगे तथा उन्हें यह जानकारी देंगे कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य जून माह से ही शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा, बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजना आवश्यक है, ताकि वे शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़े रहें और नए शैक्षिक सत्र का पूरा लाभ उठा सकें।

घर के सामने गेट लगाने पर पीड़ित ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। तहसील भोगनीपुर के थाना मूसानगर क्षेत्र के ग्राम बम्हरौली निवासी एक ग्रामीण ने गांव के ही एक व्यक्ति पर उसके घर के सामने जबरन गेट लगाकर रास्ता अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से कर कार्रवाई की मांग की है।

ग्राम बम्हरौली,निवासी रामप्रताप पुत्र शिवराम ने दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि गांव के निवासी दिनेश तिवारी (कोटेदार) ने उसके घर के सामने गेट लगवा दिया है, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। पीड़ित का कहना है कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वह स्वयं गेट हटवाने में सक्षम नहीं है। रामप्रताप ने बताया कि उसके बच्चे गुजरात के सूरत शहर में नौकरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। आरोप है कि जब उन्होंने गेट हटाने की बात कही तो दिनेश तिवारी ने गाली-गलौज की और मारपीट पर आमादा हो गया। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि उसके घर के सामने लगाए गए गेट को हटवाकर रास्ता खाली कराया जाए, जिससे उसे और उसके परिवार को आवागमन में होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। मामले में भोगनीपुर के उपजिलाधिकारी देवेंद्र कुमार का कहना है कि शिकायत मिल चुकी है जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

संविलियन विद्यालय में रोली-तिलक लगाकर हुआ विद्यार्थियों का स्वागत

» विद्यालय परिसर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राजपुर विकासखंड के संविलियन विद्यालय डेराकरीमनगर में मंगलवार को नए शैक्षिक सत्र के प्रथम दिन विद्यार्थियों का रोली-तिलक लगाकर स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के संचालन शुरू होने के साथ ही विद्यालय परिसर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला।गर्मी की छुट्टियों के बाद बड़ी संख्या में बच्चे निर्धारित ड्रेस पहनकर विद्यालय पहुंचे।

अवकाश के दौरान कक्षाओं और विद्यालय परिसर में धूल जमा हो गई थी। ऐसे में पहले दिन विद्यालय में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाकर सभी कक्षाओं को व्यवस्थित किया गया और शिक्षण कार्य की तैयारियां पूरी की गईं।प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को मीठा आहार परोसा गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक अंशुल गुप्ता, सुरेंद्र कटियार, ममता देवी, प्रमोद सिंह तथा अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। शिक्षकों ने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय में नए सत्र की शुरुआत उत्साहपूर्ण वातावरण में हुई, जिससे बच्चों और शिक्षकों में विशेष उत्साह देखने को मिला।

प्रयागराज में परिवार के तीन लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर उतारा मौत के घाट

मेजा थाना क्षेत्र के कुकुरकटवा गांव में वारदात, दो महिलाओं समेत तीन की हत्या; प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश के एंगल पर जांच तेज

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

प्रयागराज। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र स्थित कुकुरकटवा गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सोमवार देर रात हुई इस वारदात में दो महिलाओं समेत तीन लोगों को धारदार और भारी हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्यारों ने कथित तौर पर पीड़ितों को घर के भीतर और बाहर तक दौड़ा-दौड़ाकर हमला किया, जिससे घटनास्थल खून से लथपथ हो गया।मंगलवार सुबह पड़ोसियों को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के आहाते से लेकर बाहर तक तीन शव बरामद किए। मृतकों की पहचान श्यामलाल गुप्ता उर्फ कल्लू (65) तथा उनके दो भाइयों की पत्नियों के रूप में हुई है। तीनों के सिर पर कुल्हाड़ी या किसी भारी धारदार वस्तु से वार किए जाने की आशंका जताई जा रही है।घटना के समय घर में चार लोग मौजूद थे। एक 60 वर्षीय महिला भी घर में थी, जो सुरक्षित मिली है। पुलिस के अनुसार महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही है और उससे भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। मृतकों के परिजनों ने पड़ोस के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आरोपी ने करीब एक सप्ताह पहले पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस को दी गई तहरीर में प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश का भी उल्लेख किया गया है।सूचना मिलते ही डीसीपी यमुनापार विवेक चंद्र यादव, एसीपी मेजा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वायड और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया कि नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मामले की जांच के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। तिहरे हत्याकांड के बाद गांव में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है।

तीन किमी तक ट्रैक्टर में फंसी घिसटती रही कार

पति-पत्नी और भांजी की मौके पर दर्दनाक मौत

» हरिद्वार से लौट रहे परिवार की वैगनआर ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से घुसी,

» चालक को हादसे का पता न चला, दो बच्चे और एक रिश्तेदार गंभीर घायल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

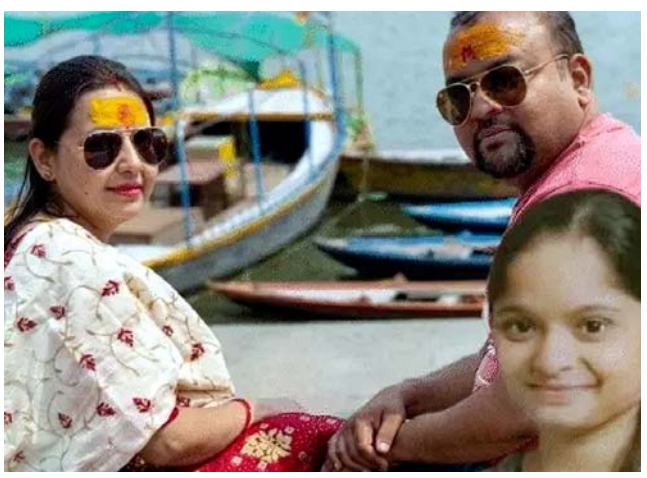

हादसे में क्षतिग्रस्त गाड़ी

लखीमपुर खीरी/हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई-लखीमपुर सीमा क्षेत्र में सोमवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। हरिद्वार से लौट रहे एक परिवार की वैगनआर कार पीछे से ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा घुसी और उसमें फंस गई। हादसे के बाद भी ट्रैक्टर चालक को इसकी जानकारी नहीं हो सकी और वह कार को करीब तीन किलोमीटर तक घसीटते हुए लखीमपुर खीरी के मैगलगंज क्षेत्र तक ले गया। इस दुर्घटना में पति-पत्नी और उनकी भांजी की मौत हो गई, जबकि दो बच्चे और एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतकों की पहचान हरदोई सिंचाई विभाग में कैशियर के पद पर कार्यरत विमल सिंह (40), उनकी पत्नी वंदना सिंह पटेल (30) तथा भांजी आलीख्या वर्मा (22) के रूप में हुई है। परिवार मूल रूप से सुल्तानपुर के शास्त्री नगर का निवासी बताया गया है और छुट्टियां मनाकर हरिद्वार से लौट रहा था।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर-ट्रॉली में नमक की बोरियां लदी थीं। कार के ट्रॉली में फंसने के बाद उसमें सवार लोग मदद के लिए चीखते-चिल्लाते रहे, लेकिन ट्रैक्टर चालक तक उनकी आवाज नहीं पहुंच सकी। बाद में एक डीसीएम चालक ने ट्रैक्टर को ओवरटेक कर चालक को हादसे की जानकारी दी। इसके बाद ट्रैक्टर रोका गया और स्थानीय लोगों ने कार के दरवाजे व शीशे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला।सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को पसगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने विमल, वंदना और आलीख्या को मृत घोषित कर दिया। विमल के बेटे वीर और बेटी रुबी के पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि उनके साले के सीने में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में कार की तेज रफ्तार हादसे का प्रमुख कारण प्रतीत हो रही है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

बाघ ने ली एक और जान

ग्रामीणों में दहशत का आलम

» खेत में चारा लेने गई महिला को उठाकर ले गया बाघ, अधखाया शव बरामद

मृतका कोकिला देवी की फाइल फोटो

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। दुधवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में इंसान और बाघ के बीच बढ़ता संघर्ष लगातार भयावह होता जा रहा है। सोमवार शाम मझगई क्षेत्र के खालेपुरवा गांव में एक महिला की बाघ के हमले में मौत ने एक बार फिर वन विभाग की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

खालेपुरवा गांव निवासी 50 वर्षीय कोकिला देवी रोज की तरह पशुओं के लिए चारा लेने खेत की ओर गई थीं। शाम ढल रही थी और खेतों के आसपास सन्नाटा बढ़ने लगा था। इसी बीच घात लगाए बैठे बाघ ने उन पर हमला बोल दिया। आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर दौड़ लगाई, लेकिन तब तक बाघ महिला को घसीटते हुए जंगल की ओर ले जा चुका था। ग्रामीणों ने काफी देर तक तलाश की। आखिरकार घटना स्थल से कुछ दूरी पर महिला का शव मिला। घटना के बाद गांव में मातम के साथ-साथ दहशत का माहौल भी फैल गया। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से बाघ की मौजूदगी देखी जा रही थी, लेकिन प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। यह घटना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जिस समय यह हादसा हुआ, उसी दिन वन्यजीव और मानव संघर्ष को लेकर उच्च स्तरीय मंथन चल रहा था। वन विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञ भविष्य की रणनीति पर विचार कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर एक परिवार अपनी सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा था।

पिछले 24 घंटों के भीतर क्षेत्र में बाघ के हमले की यह दूसरी जानलेवा घटना है। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों का धैर्य जवाब देने लगा है। लोग खेतों में जाने से डर रहे हैं और बच्चों को घरों से बाहर निकलने से रोका जा रहा है। वन विभाग की और से मृतका के पति को तत्काल सहायता के रूप में 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की गई है। साथ ही बाघ की निगरानी और उसे पकड़ने के लिए क्षेत्र में तीन पिंजरे लगाए गए हैं। विभागीय टीम लगातार गश्त कर रही है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। हालांकि ग्रामीणों की मांग है कि केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ऐसा स्थायी समाधान निकाला जाए जिससे गांवों में रहने वाले लोगों की जान सुरक्षित रह सके। फिलहाल खालेपुरवा और आसपास के गांवों में डर का साया पसरा हुआ है। ग्रामीणों की नजरें अब वन विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

सवा लाख आमों के महाभोग से सजे ठाकुर जी अलौकिक दर्शन को उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

मथुरा और गोवर्धन के प्रमुख मंदिरों में आम्रकुंज मनोरथ का भव्य आयोजन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मथुरा। ब्रजभूमि में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के बीच ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने और उनका विशेष श्रृंगार करने के लिए विभिन्न धार्मिक आयोजनों का क्रम जारी है। इसी कड़ी में मथुरा और गोवर्धन के प्रमुख मंदिरों में सवा लाख रसीले आमों का महाभोग अर्पित किया गया। आम्रकुंज मनोरथ के नाम से आयोजित इस भव्य उत्सव में ठाकुर जी के मनोहारी दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।

गोवर्धन की तलहटी स्थित जतीपुरा के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में सवा लाख से अधिक आमों से आकर्षक सजावट की गई। देश के विभिन्न राज्यों से मंगाए गए चुनिंदा आमों को गर्भगृह और मंदिर परिसर में इस प्रकार सजाया गया कि पूरा मंदिर आमों के महल जैसा दिखाई देने लगा। रंग-बिरंगे और सुगंधित आमों के बीच विराजमान ठाकुर जी की छवि ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

उधर, मथुरा के निकुंज राय मंदिर में भी सवा लाख आमों का महाभोग लगाया गया। मंदिर प्रशासन और सेवायतों ने हापुस, लंगड़ा, दशहरी, चौसा तथा सफेदा समेत आम की विभिन्न प्रजातियों को कलात्मक ढंग से सजाकर ठाकुर जी को अर्पित किया। आमों की भीनी-भीनी सुगंध से पूरा मंदिर परिसर महक उठा और भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति हुई।

मंदिर के पुजारी दाउ दयाल ने बताया कि अधिक मास के उपलक्ष्य में यह विशेष मनोरथ आयोजित किया गया है। देशभर के वैष्णव श्रद्धालुओं के सहयोग से सवा लाख आमों की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि भोग अर्पित होने के बाद सभी आमों को प्रसाद स्वरूप श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। मंदिरों के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। जय श्रीनाथ और राधे-राधे के जयघोषों के बीच भक्तों ने ठाकुर जी के दुर्लभ दर्शन किए। धार्मिक मान्यता है कि ग्रीष्म ऋतु में आम का भोग लगाने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं।

‘शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और भविष्य निर्माण का माध्यम’

ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को आधुनिक, संस्कारयुक्त और रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है श्रीराम जानकी महाविद्यालय : डॉ. एके शुक्ला

समीर शाही/ स्वराज इंडिया

स्वराज इंडिया विशेष साक्षात्कार

अयोध्या। अयोध्या के रामनगर अमावासूफी स्थित श्रीराम जानकी महाविद्यालय ने सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। आधुनिक पाठ्यक्रमों, छात्रहितैषी सुविधाओं, न्यूनतम शुल्क और बेटियों के लिए निःशुल्क शिक्षा जैसी योजनाओं के कारण यह संस्थान तेजी से विद्यार्थियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इन्हीं विषयों पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एके. शुक्ला से स्वराज इंडिया के ब्यूरो चीफ समीर शाही ने विशेष बातचीत की।

प्रश्न - इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं और विद्यार्थियों को कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध होंगे?

डॉ. एके. शुक्ला- महाविद्यालय में 18 मई से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहां स्नातक, परास्नातक, शिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के अनेक पाठ्यक्रम संचालित हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी कृषि, गृहविज्ञान, बीएड, बीपीएड, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएससी कृषि, एमएसडब्ल्यू, बीलिब, एमलिब, बीसीए, डीएलएड, आईटीआई और बीवोक जैसे पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। हमारा प्रयास है कि छात्र अपनी रुचि और भविष्य की संभावनाओं के अनुरूप विषयों का चयन कर सकें।

प्रश्न-आज के प्रतिस्पर्धी दौर में आधुनिक एवं रोजगारपरक शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और आपका संस्थान इस दिशा में क्या कर रहा है?

डॉ. शुक्ला - आज केवल पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इनवायरमेंटल साइंस जैसे आधुनिक विषयों को भी शामिल किया है। बीवोक के अंतर्गत जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन तथा फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स युवाओं को सीधे रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि विद्यार्थी डिग्री लेने के बाद नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि अवसर पैदा करने वाले बनें।

प्रश्न-छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की घोषणा चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके पीछे क्या सोच है?

डॉ. शुक्ला-बेटियों की शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार होती है। इसी सोच के साथ ÷बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ÷ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी कृषि और गृहविज्ञान में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रथम से अंतिम सेमेस्टर तक निःशुल्क शिक्षा देने का निर्णय लिया है। हमारा मानना है कि आर्थिक अभाव किसी बेटी की शिक्षा में बाधा नहीं बनना चाहिए। यह पहल ग्रामीण क्षेत्र की हजारों छात्राओं के लिए वरदान साबित होगी।

प्रश्न -विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए महाविद्यालय कौन-कौन सी विशेष सुविधाएं प्रदान कर रहा है?

डॉ. शुक्ला-हमने छात्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क बैग, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएं और पेन उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी पाठ्यक्रमों में प्रयोगात्मक शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगले तीन वर्षों तक शुल्क वृद्धि नहीं करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य और केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ तथा डिजी शक्ति योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को स्मार्टफोन एवं टैबलेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रश्न-अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश है?

डॉ. शुक्ला - शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। श्रीराम जानकी महाविद्यालय का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को श्रेष्ठ अनुशासन, नैतिक संस्कार, उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम और उज्ज्वल करियर प्रदान करना है।

मैं सभी अभिभावकों से अपील करता हूं कि वे अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए समय रहते

प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराएं। हमारा विश्वास है कि यहां से निकलने वाला प्रत्येक विद्यार्थी समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

गांव के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने वाला शिक्षा का केंद्र बन रहा है श्रीराम जानकी महाविद्यालय

डॉ0 ए के शुक्ला प्राचार्य

हाइलाइट्स

- सत्यमेव जयते के आदर्श पर आगे बढ़ रहा संस्थान
- छात्राओं को प्रथम से अंतिम सेमेस्टर तक नि:शुल्क शिक्षा
- जर्नलिज्म, फैशन डिजाइन सहित आधुनिक रोजगारपरक कोर्स
- नि:शुल्क बैग, पुस्तकें, कॉपी और पेन
- प्रयोगात्मक शुल्क पूरी तरह माफ
- तीन वर्षों तक शुल्क वृद्धि नहीं
- छात्रवृत्ति, स्मार्टफोन और टैबलेट की सुविधा
- ग्रामीण युवाओं के लिए उच्च शिक्षा और रोजगार का मजबूत मंच

स्ट्रीट लाइट में घोटाले की आहट!

12 वार्डों में काम कराने वाले ठेकेदारों का भुगतान अटका, सीओ से लगाई गुहार

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। नगर निगम के 12 वार्डों में मुख्यमंत्री त्वरित योजना के तहत लगाई गई स्ट्रीट लाइटों का भुगतान न होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 76 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का ठेका मार्टिन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, जिसने कार्य को 12 स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से पूरा कराया।

आरोप है कि काम पूरा होने के बावजूद 12 ठेकेदारों का लगभग ढाई करोड़ रुपये का भुगतान अब तक लंबित है। ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने कई बार महापौर और नगर आयुक्त से शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।

भुगतान न मिलने से परेशान सभी 12 ठेकेदारों ने एकजुट होकर सीओ अयोध्या को शिकायत पत्र सौंपा है और मामले की जांच कर बकाया धनराशि दिलाने की मांग की है। अब यह मामला नगर निगम की कार्यप्रणाली और ठेका व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। ठेकेदारों को उम्मीद है कि प्रशासन हस्तक्षेप कर जल्द भुगतान सुनिश्चित करेगा।

महिलाओं से वस्त्र बदलने के लिए नहीं लिया जाता कोई शुल्क, निजी टेंटों से रहें सावधान

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। सरयू तट पर संचालित चेंजिंग रूम को लेकर उठे विवाद के बीच नगर निगम

» सरयू तट के चेंजिंग रूम पर नगर निगम की सफाई

ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ ने बताया कि सरयू तट पर दिखाई देने वाले टेंटनुमा अथवा नीले रंग के अस्थायी चेंजिंग रूम नगर निगम द्वारा संचालित नहीं हैं। नगर निगम के अधिकृत चेंजिंग रूम अलग हैं और उनमें महिलाओं से वस्त्र बदलने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता।

उन्होंने बताया कि सरयू तट पर नगर निगम के लगभग 50 स्थायी चेंजिंग रूम उपलब्ध हैं, जिनका श्रद्धालु महिलाएं निःशुल्क उपयोग कर सकती हैं। डॉ. नागेंद्र नाथ ने कहा कि महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार के नेतृत्व में बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए और अधिक चेंजिंग रूम विकसित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। नगर निगम ने महिला श्रद्धालुओं से केवल अधिकृत एवं स्थायी चेंजिंग रूम का उपयोग करने तथा निजी या अस्थायी व्यवस्थाओं से सावधान रहने की अपील की है।

अमेरिका का कीमती विमान बी-52 बॉम्बर क्रैश, 8 की मौत

कैलिफोर्निया के एयर फोर्स बेस के पास हुआ हादसा, विमान में सवार सभी लोगों की गई जान

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मंगलवार को एक भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। अमेरिकी वायुसेना का अत्याधुनिक और लंबे समय से सेवा दे रहा बी-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर विमान उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस के निकट हुआ, जिसमें विमान में सवार सभी आठ लोगों की मौत हो गई।

अमेरिकी वायुसेना के अनुसार, दुर्घटना स्थानीय समयानुसार सोमवार सुबह करीब 11:20 बजे हुई। विमान नियमित परीक्षण मिशन पर था और एयर फोर्स बेस से उड़ान भरने के तुरंत बाद नियंत्रण खो बैठा।हादसा इतना भयावह था कि विमान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया और घटनास्थल पर आग की लपटें उठने लगीं। मृतकों में वायुसेना के जवानों के अलावा इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल थे। दुर्घटना के बाद सामने आए वीडियो और तस्वीरों में विमान का मलबा रेगिस्तानी इलाके में बिखरा दिखाई दिया।अधिकारियों ने बताया कि हादसे में किसी के बचने की

कोई संभावना नहीं थी।

एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस के 412वें टेस्ट विंग के डिप्टी कमांडर कर्नल जेम्स हेस ने कहा कि यह वायुसेना के लिए बेहद दुखद क्षण है और हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।एविएशन सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि विमान टेकऑफ के बाद पर्याप्त ऊंचाई हासिल नहीं कर सका, जिससे फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी, इंजन फेल होने या परीक्षण के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे किसी उपकरण में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियां ब्लैक बॉक्स और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी हैं।बी-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस अमेरिकी वायुसेना का सबसे प्रतिष्ठित रणनीतिक बॉम्बर माना जाता है।

यह परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है और दशकों से अमेरिका की सैन्य शक्ति का अहम हिस्सा रहा है। हाल के वर्षों में इस विमान को आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया था, जिसके बावजूद हुई यह दुर्घटना कई सवाल खड़े कर रही है।

अमेरिका-ईरान समझौते की राह में सबसे बड़ी अड़चन 300 अरब डॉलर

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी तनाव और सैन्य टकराव को समाप्त करने की दिशा में एक संभावित शांति समझौते का मसौदा तैयार होने की खबरें सामने आई हैं। इस प्रस्तावित समझौते का सबसे अहम और विवादित पहलू करीब 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज है। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई, प्रतिबंधों में राहत और विदेशों में जब्त अपनी संपत्तियों की वापसी की मांग कर रहा है, जबकि अमेरिका इसे क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक पुनर्निर्माण से जोड़कर देख रहा है। हालांकि इस पैकेज की अलग-अलग व्याख्याएं ही समझौते की सबसे कमजोर कड़ी बनती नजर आ रही हैं।

ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तेहरान ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थायी शांति समझौते के लिए व्यापक आर्थिक राहत अनिवार्य होगी। ईरान का दावा है कि युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की आवश्यकता है और इसी आधार पर उसने पुनर्निर्माण पैकेज की मांग रखी है। ईरानी नेतृत्व का मानना है कि पर्याप्त आर्थिक सहायता के बिना कोई भी समझौता लंबे समय तक टिकाऊ साबित नहीं होगा।दूसरी ओर अमेरिकी और पश्चिमी सूत्रों का कहना है कि यह राशि सीधे मुआवजे के रूप में नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेश, निजी पूंजी और पुनर्निर्माण परियोजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि किसी भी समझौते के तहत प्रत्यक्ष नकद भुगतान की संभावना बेहद सीमित है। वाशिंगटन का जोर निवेश और विकास आधारित मॉडल पर है, न कि युद्ध क्षति के औपचारिक मुआवजे पर। ट्रंप ने इस संभावित समझौते को अपनी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि बताते हुए दावा किया है कि इससे मध्य पूर्व में स्थिरता लौटेगी और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को राहत मिलेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर शांति प्रयासों का स्वागत करते हुए तेल आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद जताई है। अमेरिका का मानना है कि समझौता लागू होने पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भी हालात सामान्य हो सकेंगे।हालांकि इस प्रस्तावित समझौते को लेकर कई स्तरों पर संदेह बना हुआ है। अमेरिका ने अब तक 300 अरब डॉलर के आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, जबकि ईरान के भीतर कट्टरपंथी धड़े संभावित रियायतों का विरोध कर रहे हैं। वहीं इजरायल समेत क्षेत्रीय सहयोगी देशों की भी कुछ शर्तों पर आपत्तियां सामने आई हैं।

गोरखपुर में बनेगा जेल सिपाहियों का मेगा ट्रेनिंग सेंटर

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

गोरखपुर। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जेल सिपाहियों को प्रशिक्षण के लिए अब लखनऊ का रुख नहीं करना पड़ेगा। गोरखपुर में जेल विभाग का अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। जेल प्रशासन ने इसके लिए करीब नौ एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लेते हुए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है।गोरखपुर में प्रस्तावित यह केंद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा जेल प्रशिक्षण केंद्र होगा। वर्तमान में राज्य का एकमात्र जेल प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में संचालित है, जहां प्रदेश भर के जेल सिपाहियों और कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। लगातार बढ़ती भर्ती और प्रशिक्षण की जरूरतों को देखते हुए विभाग ने दूसरा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना तैयार की है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के जिलों से जुड़े जेल सिपाहियों को गोरखपुर में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के कार्मिकों का प्रशिक्षण पहले की तरह लखनऊ केंद्र में जारी रहेगा। इससे प्रशिक्षण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होने के साथ-साथ समय और संसाधनों की भी बचत होगी।जेल प्रशासन ने गोरखपुर जेल परिसर के निकट उपलब्ध विभागीय भूमि

➪ पूर्वांचल के कार्मिकों को लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, नौ एकड़ जमीन पर तैयार होगा अत्याधुनिक परिसर

को प्रशिक्षण केंद्र के लिए चिन्हित किया है। अधिकारियों का मानना है कि जमीन पहले से उपलब्ध होने के कारण परियोजना को तेजी से अमल में लाया जा सकेगा और निर्माण कार्य में अनावश्यक देरी नहीं होगी।

जेल अधीक्षक एके कुशवाहा ने बताया कि गोरखपुर में जेल सिपाहियों के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके लिए जेल परिसर के पास लगभग नौ एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सभी जेल सिपाहियों का प्रशिक्षण लखनऊ में होता है, लेकिन गोरखपुर में नया केंद्र बनने के बाद प्रदेश को दूसरा बड़ा प्रशिक्षण संस्थान मिल जाएगा।विभागीय अधिकारियों के अनुसार, आधुनिक सुविधाओं से लैस इस प्रशिक्षण केंद्र में जेल सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, मानवाधिकार, तकनीकी दक्षता और आधुनिक कारागार प्रबंधन से जुड़े विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र शुरू होने के बाद पूर्वांचल के जेल कर्मियों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

लिव-इन को बताया आधुनिक जीवनशैली हाईकोर्ट ने सुरक्षा देने से किया इनकार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बोला पुलिस सुरक्षा देना अवैध रिश्ते को परोक्ष मान्यता देने जैसा हो सकता है

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

चंडीगढ़। लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लिव-इन संबंध आधुनिक जीवनशैली का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन ऐसे हर रिश्ते को स्वत: कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। अदालत ने एक जोड़े की सुरक्षा संबंधी याचिका खारिज करते हुए कहा कि पुलिस को सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश देना किसी अवैध संबंध को परोक्ष रूप से मान्यता देने के समान हो सकता है।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति संदीप मौडगिल ने कहा कि भारतीय समाज में विवाह को अत्यंत पवित्र और सम्मानित संस्था माना जाता है। हालांकि समय के साथ समाज के एक वर्ग ने लिव-इन रिलेशनशिप जैसी आधुनिक जीवनशैली को अपनाया है, लेकिन ऐसे संबंधों को कानूनी संरक्षण देने के लिए निर्धारित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। याचिकाकर्ता युवक-युवती ने अदालत को बताया था कि वे बालिग हैं और लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। उनका आरोप था कि परिवार के सदस्य और रिश्तेदार उन्हें परेशान कर रहे हैं तथा युवती के परिजन उस पर संबंध समाप्त करने का दबाव बना रहे हैं। इसी आधार पर दोनों ने सुरक्षा की मांग करते हुए

हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन किसी संबंध को कानूनी रूप से स्वीकार करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय आधार होना चाहिए। केवल कुछ समय तक साथ रहने या स्वयं को लिव-इन रिलेशनशिप में बताने मात्र से अदालत ऐसे संबंध को वैध नहीं मान सकती।

कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने भविष्य में विवाह करने की बात कही है, जबकि उनमें से एक की आयु अभी वैधानिक विवाह योग्य आयु से कम है। ऐसे में उनके संबंध को कानूनी संरक्षण देने का कोई ठोस आधार नहीं बनता।न्यायमूर्ति मौडगिल ने अपने आदेश में कहा कि कई पूर्व मामलों में भी अदालतों ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को सुरक्षा देने से इनकार किया है। उनका मानना रहा है कि ऐसे मामलों में न्यायालय को समाज के व्यापक हितों और सामाजिक संरचना पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि घर छोड़कर जाने वाले युवक-युवतियां कई बार अपने माता-पिता के सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं। इसलिए केवल अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देकर हर मामले में सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती।इन्हीं टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर-208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86739 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com